FATF की रिपोर्ट

हालिया संदर्भ :

- हाल ही में वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी वित्त पोषण निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानि FATF ने भारत के लिए पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया।
- इस रिपोर्ट में भारत को पूर्व की तरह नियमित "अनुवर्ती श्रेणी" में ही रखा गया है लेकिन FATF द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जिसमें सुधार की गुंजाइश है।
- यह क्षेत्र है – आतंकी वितपोषण एवं मनी लांड्रिंग के मामलों में अभियोजन को मजबूत करना, गैर–लाभकारी क्षेत्र को आतंकवादी उपयोग से बचाना एवं निवारक उपायों का बेहतर पर्यवेक्षण तथा कार्यान्वयन।

भारत की सदस्यता और FATF :

- FATF एक अंतर सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1989 में G–7 देशों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए किया गया था।
- 2001 में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए किया गया।
- वर्तमान में यह एक 40 सदस्यीय (देश)निकाय है, जिसने देश को अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार किया है।
- इन उपायों में 40 अनुशंसाओं को शामिल किया गया है, जिन्हें 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

- यह क्षेत्र हैं –

1. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नीति
2. आतंकी वित्त
3. मनी लॉन्ड्रिंग एवं जब्ती
4. निवारक उपाय
5. सक्षम प्राधिकार एवं शक्तियां
6. कानूनी पारदर्शिता
7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- भारत 2020 में FATF का सदस्य देश बना।
- हालिया रिपोर्ट से पूर्व FATF ने जून 2010 में भारत के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया था और तब भी भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया था।

पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट :

- यह एक गहन देश आधारित रिपोर्ट है, जो FATF के विभिन्न मानदंडों के कार्यान्वयन एवं प्रभाविता का विश्लेषण करता है।
- यह रिपोर्ट वास्तव में पारस्परिक समीक्षा है, जिसमें सभी सदस्य देश एक–दूसरे देश की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तथा सुधार के लिए सिफारिश देते हैं।

रैंकिंग का महत्व :

- "नियमित अनुवर्ती श्रेणी" में शामिल होना भारत के लिए अनुकूल परिणाम के रूप में है क्योंकि कुछ विकसित देशों ने इस पर आपत्ति जताई थी।
- वर्तमान में "नियमित अनुवर्ती श्रेणी" में G–20 के के केवल चार अन्य देश UK,फ्रांस, इटली एवं रूस (2023 में FATF से निलंबित कर दिया गया है) शामिल है।
- ज्यादातर विकासशील देशों को "बढी हुई अनुवर्ती श्रेणी" में रखा गया है, जिन्हें वार्षिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट FATF के पास प्रस्तुत करना होता है, जबकि "अनुवर्ती" श्रेणी वाले देश को ऐसा 3 वर्ष में एक बार करना होता है।

चिंता का विषय :

- FATF ने इस रिपोर्ट में कहा कि भारत में मनी लांड्रिंग के मुख्य स्रोत देश के आंतरिक भागों से उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही भारत को पूर्वोत्तर एवं उत्तर में क्षेत्रीय विद्रोह तथा वामपंथी उग्रवादी समूहों से आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों का सामना करना पड़ रहा है।
- जम्मू कश्मीर और इसके आसपास में सक्रिय IS (इस्लामिक स्टेट) एवं अल–कायदा समूहों से सर्वाधिक आतंकी खतरा व्याप्त है।

Result Mitra TM

- भारत में मनी लांड्रिंग के सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, मादक पदार्थ एवं मानव–तस्करी तथा भ्रष्टाचार शामिल है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि 2014– 2022 के दौरान कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने के कारण धन शोधन निवारण एक्ट (PMLA) से संबंधित मामलों के अभियोजन में बढ़ाएं उत्पन्न हुई।
- 2018 से 2023 में FATF टीम के दौरे के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) केवल 28 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दो सिद्धि सुनिश्चित कर पाया।

Result Mitra